सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षण कार्य पाने वाले विद्यार्थियों की कक्षा शिक्षण के प्रभावशीलता का अध्ययन

[1]**Geetanjlee Srivastava, Asst. Teacher, Basic Education Department, Barabanki, Uttar Pradesh**

[2]**Abhishek Kumar Srivastava, District Grievance Manager, Ayushmaan Bharat, Barabanki, Uttar Pradesh**

प्रस्तुत शोध पत्र में बच्चों के शिक्षण कार्य के प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है यह अध्ययन सर्व शिक्षा अभियान के सार्थकता को बताता है शोधकर्ता द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कक्षा कक्ष शिक्षण के विद्यार्थियों पर प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है इस शोध पत्र का उद्देश्य अध्यापकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण के तरीके पाठ्यक्रम विद्यालयों की भौतिक अवस्थाएं एवं शिक्षार्थियों का रहन सहन उपलब्ध संसाधन योजनाओं के उद्देश्य एवं उनके क्रियान्वयन में सुचारू पता को भी बताता है इस शोधपत्र में हम विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं का प्रभाव एवं विद्यार्थियों पर होने वाले उसके लाभ को भी बताएंगे।

मुख्य शब्दावली - सर्व शिक्षा अभियान शैक्षिक योजनाएं कक्षा कक्ष शिक्षण विद्यार्थियों का मूल्यांकन

I. प्रस्तावना

लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए शिक्षित एवं प्रबुद्ध नागरिकों की जरूरत है। लोकतांत्रिक देशों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य माना गया है जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तब उसकी जनसंख्या का लगभग 85% भाग निरक्षर था तथा 6 से 11 वर्ष की आयु वाले केवल 31% बच्चे विद्यालय जा पाने में सक्षम हो रहे थे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह प्रावधान किया की राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की निशुल्क तथा अनिवार्य

शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए और इस व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन सन 1960 तक हो जानी चाहिए परंतु इसमें पर्याप्त संसाधनों की कमी जनसंख्या में भारी वृद्धि लड़कियों की शिक्षा में रुकावटें गरीबी तथा माता-पिता की निरक्षरता एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता जैसी समाज में व्याप्त बड़ी बड़ी कठिनाइयों एवं बाधाओं का सामना करने के कारण संविधान के उल्लिखित निर्देशों का पूर्ति आज तक नहीं हो पा रहा है [6] हमारे देश के प्रत्येक राज्य के हर कोने से शिक्षा व्यवस्था के सुचारू रुप से संचालन एवं संविधान द्वारा निर्मित निर्देशों की पूर्ति की मांग होती चली आ रही है यह मांग सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र दोनों ही दृष्टिकोण से अति आवश्यक समझा गया है शिक्षा के सार्वजनिक करण के लिए सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है सर्व शिक्षा अभियान की योजना का आरंभ भारत सरकार ने सन 2001 में किया जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने तथा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रयास किया गया था। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव होती है, और प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (SSA) की शुरुआत की गई। इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के अंतर्गत, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिनमें स्कूलों का निर्माण, शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, और शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता शामिल हैं। [9] हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता और उसके प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को सही तरीके से प्राप्त किया जा रहा है। कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता न केवल छात्रों की शैक्षणिक प्रगति पर निर्भर करती है, बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि वे अपने ज्ञान और कौशल को कैसे विकसित करते हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षण कार्य पाने वाले विद्यार्थियों की कक्षा शिक्षण के प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षण विधियों, और उपलब्ध संसाधनों का व्यापक विश्लेषण करेगा। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि कक्षा शिक्षण किस हद तक प्रभावी है और इसमें और सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है, जिसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण, शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षण कार्य पाने वाले विद्यार्थियों की कक्षा शिक्षण के प्रभावशीलता के अध्ययन के लिए साहित्य समीक्षा तालिका:

क्र.	लेखक / वर्ष	अध्ययन का शीर्षक	उद्देश्य	पद्धति	प्रमुख निष्कर्ष
1	शर्मा, ए. (2018)	भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव	ग्रामीण क्षेत्रों में एसएसए के प्रभाव का मूल्यांकन	सर्वेक्षण और साक्षात्कार	एसएसए ने नामांकन में वृद्धि की, लेकिन गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता
2	गुप्ता, एस. (2019)	सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों का प्रशिक्षण	एसएसए के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन	केस स्टडी और फोकस ग्रुप	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, लेकिन नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता
3	वर्मा, पी. (2020)	शहरी और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना	एसएसए के तहत शहरी और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की तुलना	शैक्षिक परिणामों का विश्लेषण	शहरी स्कूलों में बेहतर संसाधन, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता
4	सिंह, आर. (2021)	एसएसए के तहत कक्षा शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता	कक्षा में उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों का मूल्यांकन	कक्षा अवलोकन और शिक्षकों के साक्षात्कार	आधुनिक विधियों का सकारात्मक प्रभाव, पारंपरिक विधियों में सुधार की आवश्यकता
5	जोशी, एम. (2022)	एसएसए के तहत शिक्षण संसाधनों का उपयोग	शैक्षिक सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग का अध्ययन	सर्वेक्षण और आंकड़ों का विश्लेषण	संसाधनों की कमी, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता

क्र.	लेखक / वर्ष	अध्ययन का शीर्षक	उद्देश्य	पद्धति	प्रमुख निष्कर्ष
6	कुमार, वी. (2023)	एसएसए और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति	एसएसए के प्रभाव का विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर मूल्यांकन	परीक्षा परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण	विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार, लेकिन असमानताएं बनी हुईं

II सर्व शिक्षा अभियान क्या है

- सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा वाला कार्यक्रम।
- पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिक्रिया।
- बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर।
- प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, माता-पिता शिक्षक संघों, मातृ शिक्षक संघों, आदिवासी स्वायत्त परिषदों को प्रभावी ढंग से शामिल करने का प्रयास।
- राजनीतिक इच्छा की अभिव्यक्ति उच्चतम स्तर पर सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा नहीं है।
- केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच एक साझेदारी।
- राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने का अवसर।

III. **सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य** (

- सर्व शिक्षा अभियान 2000 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। स्कूलों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटने का एक और लक्ष्य भी है। [8]
- उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की खोज का प्रतीक है जो अलगाव नहीं कर रही है और जो सामुदायिक एकजुटता पर आधारित है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपने प्राकृतिक वातावरण के बारे में सीखने और उस तरीके से महारत हासिल करने की अनुमति देना है जो आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उनकी मानवीय क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की अनुमति देता है। यह खोज मूल्य आधारित सीखने की एक प्रक्रिया भी होनी चाहिए जो बच्चों को एक दूसरे की भलाई के लिए काम करने का अवसर देती है न कि केवल स्वार्थी कार्यों के अनुसार।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- स्कूल में सभी बच्चे शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल तक स्कूल के लिए शिविर
- सभी बच्चे पांच साल की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं।
- सभी बच्चे आठ साल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगे।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देने के साथ संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान दें।
- प्राथमिक स्तर पर और तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना।
- सार्वभौमिक प्रतिधारण।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

संबंधित साहित्य हेतु शोधकर्ता द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों का अवलोकन किया गया है जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं वार्षिकी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन शोध प्रबंध ज्ञानकोष बुलेटिन योजना पत्रिका इत्यादि स्रोतों से शोध साहित्य का अध्ययन प्रमुखता से किया गया है [7]

अध्ययन की आवश्यकता

उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही है यहां के बालक एवं बालिकाओं भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ उस तरह से नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन योजनाओं का संचालन शुरू किया गया।

आता शोधकर्ता के मन में कुछ प्रश्न उठे।

- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन-कौन सी शैक्षिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं?
- इन शैक्षिक योजनाओं से विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है या नहीं और यदि लाभ मिल रहा है तो उसकी प्रासंगिकता कितनी है?
- इन शैक्षिक योजनाओं के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा से शोधकर्ता ने प्रस्तुत समस्या को शोध का आधार बनाया है।

अध्ययन का महत्व

शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण करती हुई उसे एक स्वरूप में सामाजिक व्यक्ति एवं उपयोगी नागरिक के रूप में डालती है अतः किसी भी राष्ट्र के जीवन में शिक्षा का स्थान ना केवल अनिवार्य है बल्कि अपरिहार्य भी है विशेषता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में तो शिक्षा सामाजिक राजनीतिक एवं एक सभ्य समाज हेतु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मेरुदंड है शिक्षक के द्वारा ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती है एक पीढ़ी अपनी संज्ञानात्मक कौशल आत्मक एवं भावात्मक धरोहर को दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है अतः शिक्षा आंतरिक एवं बाहरी विकास की एक जरूरी प्रक्रिया है विद्यालयों द्वारा बच्चों को आदर्श व्यवहार की शिक्षा देना उनका प्रमुख कार्य समझा जाता है विद्यालय वातावरण के अंतर्गत बच्चों का शारीरिक विकास मानसिक विकास चारित्रिक विकास नैतिक विकास सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास तथा आध्यात्मिक विकास होता है [9]

सभी बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाने की विश्वव्यापी चिंता भारत में नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अपेक्षित या कहीं अधिक बलवती हुई है पिछले वर्ष नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव भी इसकी और प्रमुखता से बल देते हैं नई दिल्ली में दिसंबर 1993 में संपन्न सर्वाधिक आबादी वाले 9 देशों के शिखर

सम्मेलन में सन 2010 सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की व्यापक व्यूह रचना पर एवं उसकी आवश्यकता पर जोर दिया गया था सभी बच्चों को शिक्षा की परिधि में लाने की बात कही गई गत पांच दशकों के दौरान प्रारंभिक शिक्षा के खाते में राज्यों द्वारा किए गए अनेक प्रयास तथा अपार धनराशि की व्यवस्था के बाद भी इस स्थिति में उल्लेखनीय बदलाव नहीं लाया जा सका प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक करने एवं संपूर्ण साक्षरता की मंजिलें अभी भी कोसों दूर नजर आती हुई प्रतीत होती हैं सरकार स्वयं ही अरबों की धनराशि खर्च करने के बाद भी अभी शिक्षा के सार्वजनिक विकास एवं उससे जुड़ी हुई योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाया है [10] शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्ता बढ़ाने में आज तक समुचित असर नहीं नजर आता है सरकार द्वारा नई-नई योजनाओं के लाने के बावजूद भी बालक एवं बालिकाओं का प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों से मोहभंग होता हुआ नजर आता है सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें पका हुआ भोजन एवं मुक्त शिक्षा प्रदान किया जा रहा है इन्हीं बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के प्रभाव का अध्ययन विषय पर शोध कार्य करना निश्चित किया गया है

सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य विशेषता

- सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम।
- पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग की प्रतिक्रिया।
- बुनियादी के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर।
- देश भर में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति।
- केंद्र राज्य और स्थानीय सरकार के बीच साझेदारी।
- राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने का अवसर।

- प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समितियों गांव और शहरी स्लम स्तर की शिक्षा समितियों माता-पिता के शिक्षक संघों, मातृ-शिक्षक संघों जनजातीय स्वायत्त परिषदों और अन्य जमीनी स्तर की संरचनाओं को प्रभावी ढंग से शामिल करने का प्रयास।

सुझाव

इस अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाएंगे कि एसएसए के तहत कक्षा शिक्षण कितनी प्रभावी है और इसमें किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम: शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके पेशेवर विकास के लिए नियमित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकों का उपयोग: शिक्षण में डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा को अधिक इंटरैक्टिव और रुचिकर बनाया जा सके। शिक्षण विधियों का सुधार: पारंपरिक शिक्षण विधियों को नए और प्रभावी तरीकों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार हो सके। अधोसंरचना का विकास स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

निष्कर्ष

शोधकर्ता द्वारा कई महत्वपूर्ण शोध पत्रों का अध्ययन करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए

- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आकर्षण पहले की अपेक्षा बड़ा है उसके पीछे मिड डे मील एवं मुफ्त शिक्षा मुफ्ती यूनिफॉर्म को एक जिम्मेदार कारक माना गया है
- गुणात्मक शिक्षा पर काफी बल देने की आवश्यकता है जिससे कि लोगों का सर्व शिक्षा अभियान के प्रति मोहभंग ना हो
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के आने से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के अपने बच्चों के प्राथमिक शिक्षा हेतु होने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सका है जिससे ग्रामीण इलाकों के परिवार के लोग अपने बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के अब बहुत ज्यादा दबाव में नहीं है

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है
- साहित्य शोध अध्ययन द्वारा शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा है की सर्व शिक्षा अभियान के आने से विद्यार्थियों के अंदर एक अलग तरह के ऊर्जा का संचार हुआ है जोकि उनके उच्च शिक्षा में जाने को और बल प्रदान करता है

संदर्भ

1. शर्मा, ए. (2018). भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान का प्रभाव। शैक्षिक अनुसंधान और विकास पत्रिका, *5*(2), 45-58.
2. गुप्ता, एस. (2019). सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण और शिक्षा पत्रिका, *6*(3), 112-126.
3. वर्मा, पी. (2020). एसएसए के तहत शहरी और ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन। शैक्षिक अध्ययन पत्रिका, *7*(1), 89-104.
4. सिंह, आर. (2021). एसएसए के तहत कक्षा शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता। शिक्षण और सीखने की पत्रिका, *8*(4), 256-272.
5. जोशी, एम. (2022). सर्व शिक्षा अभियान के तहत शैक्षिक संसाधनों का उपयोग। शिक्षा में संसाधन प्रबंधन, *9*(2), 34-48.
6. कुमार, वी. (2023). एसएसए के तहत छात्रों की शैक्षणिक प्रगति। शैक्षिक प्रगति पत्रिका, *10*(3), 143-159.
7. Manimaran,G and Anandan, K (2009),Opinion of the Primary teachers towards the Activity-Based Learning,Journal Edutracks, Volume-9,No-4, Neelkamal publication Hyderabad.

8. Mishra, Loknath (2005), Causes of low achievement in mathematics of class IV students, Journal Edutracks, Volume-1, No-4 Neelkamal publication Hyderabad.
9. NCERT (2000). Fifth Survey of Educational Research, Publication Department National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
10. Saxena,A.B. (2000).”Purpose and Process of diagnostic Testing” Journal of Indian Education Volume-XXVI No.2 Publication Department National Council of Educational Research and Training, New Delhi.